(1)) Does not arise.

(c) A complaint that about 9641 hags of wheal received under Indo-US Agreement and allotted to one Shri P. Sundarain hv the Church World Service, a Voluntary Agency approved by the Government, for free distribution in Koilpatti and Kadanibur towns in Tirunelveli Dis trt'ct of Tamil Nadu had been sold in ilie black market is under verification by the Centra] Bureau of Investigation, Madras. These bags were despatched bv Regional Direc-loi (Food).

(d) No official of Food Corporation of India is concerned in the matter. Appropriate action will betaken on receipt of a report from the Central Bureau of Investigation.

भांडागार निगम द्वारा खरीदा गया अनाज

594. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 तथा 1968–69 के दौरान विभिन्न राज्यों में भाण्डागार निगमों ने कितना अनाज खरीदा और कितना अनाज भाण्डागारों में सड़ गल कर बर्बाद हुआ ; और

(ख) क्या यह सच है कि भाण्डागार निगम अभी तक किसानों का विखास प्राप्त कर उनकी सहायता करने में असफल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

FOODGRAINS PURCHASED BY WAREHOUSING CORPORATION

394. SHRI j. P. YADAV: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains purchased by the Warehousing Corporation during the years 1967-68 and 1968-69 in each of the States and the value of the foodgrains which were wasted in warehouses; and

(b) whether it is a fact that the Warehousing Corporation has not been successful so far in helping the farmers bv winning over their confidence; and if so, what are the reasons therefor?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय अथवा राज्य भाण्डागार निगम कोई खाद्यान्न नहीं खरीदते हैं और इसलिए खरीदे गए खाद्यान्नों की बर्बादी के कारण हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगम का मुख्य कार्य जमाकर्ताओं को कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक संचयन विधाएं सुलभ करना है । इन निगमों के पास किसानों द्वारा रखा गया माल अधिक नहीं होता है क्योंकि भाण्डागार की रसीदों पर व्यक्तिगत किसानों को सीमित पेशगी राशि मिलती है और किसान भी अपने थोड़े स्टाक को भाण्डागारों में लाना अलाभकर समझता है ।

HI HE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a) The Central or the State Warehousing Corporations do not purchase anv foodgrains and, therefore, the question of loss on account of wastage of purchased fooderains does not arise.

(b) No, Sir. The main function of the Central and the State Warehousing Corporations is to provide \cientific storage facilities for agricultural produce and other notified

†[ ]English translation.

commodities, offered bv the depositors. The deposits made b> the farmers with the Corporations are not large because of the limit d advances available to individual farmers against warehouse receipts and also because farmers find it uneconomical to bring their small stocks to the warehouses.]

अन्न की उपज

595. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न राज्यों में अन्न की कितनी उपज हुई है और कितना अन्न आवश्यकता से कम पड़ा है ;

(ख) अन्न के मामले में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि सम्पत्ति पर कर, खाद पर कर एवं विद्युत चालित पम्पिग सैटों पर कर लगाये जाने के कारण किसानों के उत्साह में कमी आई है ?

FOOD PRomcnoN

SHRI). YADAV: Will the Minister of FOOD and AGRICULTURE be pleased lo state:

(a) the quantity of foodgrains produced in the1 various States during the past one year and so far during the current year and the quantum bv which this production fell short of the requirements;

(b) what measures have been taken by Government to encourage the farmers in order to make India self-sufficient in the matter of food; and

(c) whether it is a fact that taxes on agricultural property, fertilizers and power driven pumping sets have disheartened the farmers?]

†[ ] English translation.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) भारत में 1967–68 के दौरान राज्यवार कुल खाद्यान्नों का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। 1968–69 के लिए यह आंकड़े चालू कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त 1969 में उपलब्ध हो सकेंगे। उपभोग के वैज्ञानिक तथा वृहद् सर्वेक्षण के अभाव में तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि खाद्यान्नों का उपभोग कुछ हद तक घटता बढ़ता रहता है, यह खाद्यान्नों और अन्य एवजी खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता पर उनके तुलनात्मक मूल्य, आय के स्तर, जनसंख्या की वृद्धि तथा नगरीकरण की अवस्था पर निर्भर करता है। अतः खाद्यान्नों की मांग अथवा उसमें पड़ने वाली कमी की मात्रा के सही आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ख) सरकार खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए किसानों को खेती के विकसित साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थता प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। प्रमुख साधनों में नयी तकनीकों का अपनाया जाना, सुधरे बीज, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और कृषि मशीनों, संस्थानिक ऋण, किसानों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध और उचित मूल्यों का आश्वासन रूपी आवश्यक इन पुटों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध आदि हैं।

(ग) शक्ति चालित पम्पसेटों पर से कर हटा लिया गया है। जहां तक सम्पदाकर का प्रश्न है, कृषि के लिये छूट की अलग से व्यवस्था की गई है। सरकार सन्तुष्ट है कि कर किसी भी प्रकार कृषि उत्पादन में बाधा नहीं डालेगें।